(v) NEED FOR A REMUNERATIVE PRICE FOR TOBACCO PRODUCERS

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura) : The peasants of Cooch-Bihar district of West Bengal are in dire distress due to the sharp fall of raw tobacco price. About two lakhs of peasants are involved in tobacco cultivation in the district. Where the remunerative price of tobacco should be Rs. 500 a maund (i.e. Rs. 1,250 a quintal), the peasants are being forced to sell at Rs. 50 to 60 a maund (i.e. Rs. 125 to Rs. 150) a quintal. Earlier, there was Central excise duty on raw tobacco to the tune of more than Rs. 100 a maund (i.e. Rs. 250 a quintal). The Central Government used to earn more than Rs. 5 crores from raw tobacco. The duty was abolished during the tenure of the Janata Government. But, strangely, this did not give any actual benefit to the producer peasants. It is the middle men who cornered the entire benefit. The price of raw tobacco in primary markets was depressed even further despite the abolition of duty.

The peasants have become very restless. There was road block by the peasants on the 16th March, at the call of the Kisan Sabha.

I draw the immediate attention of the Minister of Agriculture and the Minister of Commerce to take effective measures so that the tobacco producers in Cooch-Bihar and other places can be guaranteed fair price through Government purchase system at proper price.

(vi) REPROTED DISTORTED DELINEATION OF INDIA'S BOUNDARY IN THE LATEST CHINESE MAP.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): The latest Chinese maps not only continue to show a distorted delineation of the boundary in all the sectors, but also mark out "Sikkim" as an independent state. For instance, a publication "Which : 1980" described "Sikkim" as an independent State on China's southern borders, as do "An Outline of Chinese Geography" and "China—a General Survey".

In all these publications, the former Sikkimese flag of 'Independent Sikkim' and the Tibetan prayer wheel, as the State's symbol, have been mentioned. In the 1980 publication, moreover, Sikkim's area has been given as 7,100 sq. Kilo metres, while according to Indian Geography textbooks it is 7,300 sq. Kilo metres.

The Finance Minister of Sikkim is reported to have told the Assembly that the Indian Constitution was not applicable to Sikkim until the old laws of the erstwhile Chogyal regime were repealed by a competent legislature.

I would therefore, request the Government to clarify whether Government accepts the statement of the Finance Minister of Sikkim and regarding the distorted delineation of the boundary shown in Chinese maps.

(vii) REPORTED DIGGING OF A NEW DRAIN BY DELHI ADMINISTRATION FOR RELEASE OF WATER FROM HARYANA AND RAJESTHAN AND FARMER'S REACTION THERETO.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं —

दिल्ली प्रशासन द्वारा हरियाणा एवं राजस्थान की विभिन्न नदियों एवं नालों के पानी को मोड़ कर दिल्ली के देहाती क्षेत्र से निकाल कर यमुना नदी में डालने की योजना है । इसलिए आठ सौ फीट चौड़ा और छत्तीस किलोमीटर लम्बा नाला खोदा

जायगा जिस के लिए साढ़े सत्रह सौ एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जायगा जो जमीन बिलकुल उपजाऊ है। इस नाला खोदाई योजना को लेकर किसानों में काफ़ी रोष है। संभव है जमीन अधिग्रहण के समय अप्रिय घटना भी घट जाय। इस सम्बन्ध में किसानों के प्रतिनिधि ने उपराज्यपाल, दिल्ली एवं प्रधान मंत्री से भी पिछले माह मिल कर अपनी समस्या को रखा था।

किसानों की मांग हैं कि वर्तमान नाले को ही यदि आवश्यकता हो तो चौड़ा किया जाय और नया नाला निकालने की अव्यवहारिक एवं किसान विरोधी योजना को रद्द किया जाय। इस सम्बन्ध में किसान 25 मार्च, 81 से बोट क्लब पर भूख हड़ताल पर भी जा रहे हैं।

सरकार इस सम्बन्ध में कार्रवाई कर सदन को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

14.23 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1981-82—*Contd.*

MINISTRY OF COMMERCE—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER

Shri Krishna Kumar Goyal.

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, वाणिज्य मंत्रालय पर कल से बहस चल रही है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने ट्रेड डेफिसिट के बारे में चिन्ता व्यक्त की है उनके साथ अपने आप को जोड़ते हुए मैं अपने विचार यहां पर रखना चाहूंगा। यदि यह कहा जाए कि वाणिज्य मंत्रालय—उसके काम करने का ढंग और उसकी उपलब्धियां, हमारे देश के आर्थिक तन्त्र की मेरुदण्ड हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह इस विभाग की ही परफार्मेंस है जिससे आर्थिक क्षेत्र में दुनियां के बाजारों में हमारे देश की साख बनती या बिगड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1975–76 में, जिसको कि इमर्जेन्सी का गोल्डेन पीरियड कहा जाता है, व्यापार में 1222 करोड़ का घाटा हुआ था। गत वर्ष 1979–80 में यह व्यापारिक घाटा 2328.2 करोड़ हुआ और इस साल 1980–81 में व्यापार का घाटा 4200 करोड़ तक पहुंचने की सम्भावना है। इस प्रकार से लगातार व्यापार में ट्रेड डेफिसिट होता चला जाए तो उसका प्रभाव कुल मिलाकर हमारे फारेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ता है और उसका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे रूपए का जो मूल्य है उसके ऊपर पढ़ता चला जा रहा है। जो हमारे फारेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वह 1976–77 में 2863 करोड़ थे, 1977–78 में बढ़कर 4499 करोड़ हो गए, 1978–79 में 5219.9 करोड़ हो गए लेकिन 1979–80 से उसमें घटाव शुरू हुआ। 1979–80 में वह घट कर 5163.7 करोड़ रह गए और 1980–81 में जो अभीतक जनवरी तक के आंकड़े दिए गए हैं उसके हिसाब से 4850.5 करोड़ फारेन एक्सचेंज था। मैं कहना चाहूंगा कि इसके अन्दर इन्टरनेशनल मोनेटरी फंड (I. M. F.) से 800 करोड़ लिया हुआ भी जोड़ दें और उसके अलावा फरवरी-मार्च, दो महीनों में जो फारेन एक्सचेंज में और गिरावट आ सकती है और आयेगी उसको जोड़ दें तो हमारा फारेन एक्सचेंज 4 हजार करोड़ रु० से भी कम रह जाएगा। यह चिन्ता का विषय है, मैं इस पर कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जो वस्तुस्थिति है, वह